श्रीमती अपर्णा ए शाह

बनाम

मेसर्स शेठ डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड और अन्य

(2013 की आपराधिक अपील संख्या 813)

1 जुलाई, 2013

[पी सदाशिवम और जगदीश सिंह खेहर, जे.जे.]

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881:

एस.एस. 138 और 141- चेक का अनादर - संयुक्त खाताधारकों का दायित्व - शिकायत u/s. 138-माना: अंडर एस. 138, केवल "चेक जारी करने वाले को ही दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बनाया जा सकता है - दंडात्मक कानूनों की सख्त व्याख्या की आवश्यकता है - संयुक्त खाते से चेक जारी करने के मामले में, संयुक्त खाताधारक पर तब तक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जब तक कि चेक प्रत्येक संयुक्त खाताधारक द्वारा हस्ताक्षर न किए हो - अपीलकर्ता ने चेक पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं - धारा 141, जो एक कंपनी द्वारा किए गए धारा 138 के तहत अपराध से संबंधित है, आकर्षित नहीं होती है - अपीलकर्ता की शिकायत में ऐसा कभी नहीं था व्यक्तियों के एक संघ के रूप में मुकदमा चलाया जा रहा था - शब्द "व्यक्तियों के संघ" की व्याख्या धारा 141 में शामिल प्रतिवर्ती दायित्व के सिद्धांत के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए की जानी

चाहिए - अपीलकर्ता के संबंध में कार्यवाही, रद्द कर दी गई - क़ानून की व्याख्या - एजुस्डेम जेनेरिस.

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973:

धारा.482 - आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना - उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का चरण - समझाया गया।

अपीलकर्ता और उसके पति का संयुक्त खाता था। बाद वाले ने उक्त खाते से एक चेक जारी किया। चेक "अपर्याप्त धनराशि" के कारण बाउंस हो गया था। प्रतिवादी सं. की शिकायत पर. 1-अदाकारी, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने दोनों के खिलाफ प्रक्रिया जारी की। एक अदालत ने कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया। पत्नी द्वारा दायर तत्काल अपील में, अपीलकर्ता के लिए यह तर्क दिया गया था कि धारा के प्रावधान के मद्देनजर। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के 138 और बी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जारी करने की अभिव्यक्ति "आहर्ता" की व्याख्या को बरकरार नहीं रखा जा सका।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए, अभिनिर्धारित किया

1.1 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत अपराध गठित करने के लिए, सी जुगेश सहगल के मामले में इस न्यायालय ने धारा की उन सामग्रियों की गणना की, जिन्हें पूरा करना आवश्यक है। यह मामला चेक के अनादरण के कारण आपराधिक दायित्व से संबंधित है। यह मुख्य रूप से दराज पर पड़ता है; यदि यह एक कंपनी है, तो ड्रॉअर कंपनी पर और कंपनी के अधिकारियों तक विस्तारित है। आपराधिक दायित्व से जुड़े मामलों में सामान्य नियम परोक्ष दायित्व के विरुद्ध है। किसी को भी दूसरे के कार्य के लिए आपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। हालाँकि, यह सामान्य नियम दूसरों को दायित्व प्रदान करने वाले कानूनों में

किए जा रहे विशिष्ट प्रावधान के कारण अपवाद के अधीन है, उदाहरण के लिए एनआई अधिनियम की धारा 141, जिसका तत्काल मामले में कोई उपयोग नहीं होगा। दंडात्मक क़ानूनों की सख्त व्याख्या किए जाने की आवश्यकता है। [पैरा 8,13 और 23] [78-बी; 79-बी; 80-डी-एफ; 84-जी]

जुगेश सहगल बनाम शमशेर सिंह गोगी **2009 (10) एफ एससीआर 857 = (2009) 14 एससीसी 683;** और *शाम सुंदर और अन्य बनाम हरियाणा राज्य,* **1989 (3) एससीआर 886 = (1989) 4 एससीसी 630** पर भरोसा किया गया।

एस.के. अलघ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य **2008 (2) एससीआर 1088 = (2008) 5 एससीसी 662** - संदर्भित।

1.2 यह विवाद में नहीं है कि पहले प्रतिवादी ने दंड संहिता के किसी अन्य प्रावधान के तहत कोई शिकायत दर्ज नहीं की है और इसलिए, 'पार्टियों का इरादा' आकर्षित नहीं होता है। चूंकि अपीलकर्ता ने एच प्रासंगिक सामग्री संलग्न की थी, अर्थात्, नोटिस की प्रति, उत्तर की प्रति शिकायत की प्रति और आदेश जारी करने की प्रक्रिया जो अकेले ही एनआई की धारा 138 के तहत शिकायत के संबंध में विचार करने के लिए प्रासंगिक है। अधिनियम के अनुसार, यह नहीं कहा जा सकता कि भौतिक तथ्यों या प्रासंगिक तथ्यों को दबाने के लिए अपीलकर्ता के रुख को खारिज कर दिया जाना चाहिए। [पैरा 14] [81-डी, जी-एच]

ओसवाल फैट्स एंड ऑयल्स लिमिटेड बनाम अपर आयुक्त (प्रशासन), बरेली मंडल, बरेली एवं अन्य, **2010 (5) एससीआर 927 = (2010) 4 एससीसी 728**, *बलवंतराय चिमनलाल त्रिवेदी बनाम एम.एन. नागराश्ना एवं अन्य,* **एआईआर 1960 एससी 1292**,

जे.पी. बिल्डर्स एवं अन्य बनाम ए. रामदास राव और अन्य। **2010 (15) एससीआर 538 = (2011) 1 एससीसी 429** अनुपयुक्त ठहराया गया।

1.3 इसके अलावा, मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर शिकायत में पहले प्रतिवादी का मामला कभी नहीं था कि अपीलकर्ता पत्नी पर व्यक्तियों के एक संघ के रूप में मुकदमा चलाया जा रहा था। चूंकि, इस अभिव्यक्ति को परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए इसे एस में शामिल प्रतिवर्ती दायित्व के सिद्धांत के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ईजसडेम जेनेरिस की व्याख्या की जानी चाहिए। 141. रघु लक्ष्मीनारायणन के मामले में इस न्यायालय द्वारा "शिकायत", "व्यक्ति" "व्यक्तियों का संघ" "कंपनी" और "निदेशक" शब्दों की व्याख्या की गई है। इसलिए धारा 138 और वैधानिक नोटिस, उत्तर, शिकायत की प्रति, आदेश, प्रक्रिया जारी करने आदि से निकाली गई सामग्री स्पष्ट रूप से केवल चेक जारी करने वाले को ही इसके लिए जिम्मेदार दिखाती है। [पैरा 15-16] [82-सी-एफ]

रघु लक्ष्मीनारायणन बनाम फाइन ट्यूब्स, **2007 (4) एससीआर 885 (2007) 5 एससीसी 103** - पर निर्भर।

देवेन्द्र पुंडीर vs. राजेंद्र प्रसाद मौर्य, Proprietor, सत्यमेव एक्सपोर्ट्स एस/ओ. श्री रमा शंकर मौर्य, **2008 Criminal Law Journal 777**, गीता बेरी vs. जेनेसिस एजुकेशनल फाउंडेशन, **151 (2008) DLT 155,** श्रीमती बनदीप कौर vs. एस अवनीत सिंह, **(2008) 2 PLR 796** अनुमत s

1.4 इसलिए, इस न्यायालय का मानना हैं कि अधिनियम की धारा 138 के तहत, केवल चेक का "आहरणकर्ता" ही मुकदमा चलाया जा सकता है। इसके अलावा, संयुक्त खातों से चेक जारी करने के मामले में धारा 138 के तहत, संयुक्त खाता धारक पर

तब तक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जब तक कि चेक पर प्रत्येक संयुक्त खाता धारक द्वारा हस्ताक्षर न किया गया हो। मौजूदा मामले में, अपीलकर्ता चेक जारी करने वाली नहीं है और उसने उस पर हस्ताक्षर भी नहीं किए हैं। [पैरा 22-23] [84-डी-ई, एफ-जी]

2. ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रक्रिया जारी होने के बाद ही कोई व्यक्ति अपने पास उपलब्ध विभिन्न आधारों पर सी को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। इसलिए उच्च न्यायालय का यह मानना स्पष्ट रूप से गलत था कि अपीलकर्ता की प्रार्थना पर विचार भी नहीं किया जा सकता क्योंकि मुकदमा चल रहा था। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने स्वयं मजिस्ट्रेट को दस्तावेजों के डी प्रवेश/अस्वीकार की प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया है। ऐसे में यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि ट्रायल एडवांस स्टेज में है. इन परिस्थितियों में, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष लंबित अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक मामला संख्या 1171/एसएस/2009 की प्रक्रिया रद्द की जाती है। [पैरा 23 और ई 24] [85-सी-ई]

केस कानून संदर्भ:

2009 (10) SCR 857	पर भरोसा	पैरा 8
2008 (2) SCR 1088	संदर्भित	पैरा 10
1989 (3) SCR 886	पर भरोसा	पैरा 11
2010 (5) SCR 927	अनुपयुक्त ठहराया गया	पैरा 14
AIR 1960 SC 1292	अनुपयुक्त ठहराया गया	पैरा 14

2010 (15) SCR 538	अनुपयुक्त ठहराया गया	पैरा 14
2007 (4) SCR 885	पर भरोसा	पैरा 15
2008 क्रिमिनल लॉ जर्नल 777	अनुमति	पैरा 17
151 (2008) डीएलटी 155	अनुमति	पैरा19
(2008) 2 PLR 796	अनुमति	पैरा 19

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2013 की आपराधिक अपील संख्या 813।

बॉम्बे में न्यायिक उच्च न्यायालय के 2010 की आपराधिक रिट याचिका संख्या 1823 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 24.09.2010 से ।

के.वी. विश्वनाथन, निखिल गोयल, मार्सुक बफाकी, शिवराज गांवकर, मेहुल एम. गुप्ता, ए. वेनायगम बालन, अपीलकर्ता.

मुकुल रोहतगी, हुज़ेफ़ा अहमदी, महेश अग्रवाल, गौरव गोयल, ई.सी. अग्रवाला, रोहन शर्मा , उत्तरदाताओं के लिए

न्यायालय का निर्णय पी. सदाशिवम, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. स्वीकृत।

2. **यह अपील 2010 की आपराधिक रिट याचिका संख्या 1823 में बॉम्बे के उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 24.09.2010 के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका को आंशिक रूप से अनुमति दी थी।**

3. **संक्षिप्त तथ्य:**

ए) मेसर्स शेठ डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड - यहां प्रतिवादी कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय 11, वोरा पैलेस, एम.जी. रोड, कांदिवली (पश्चिम), मुंबई और भूमि विकास और निर्माण के व्यवसाय में लगी हुई है। अपर्णा ए. शाह (यहां अपीलकर्ता) और आशीष शाह, उनके पति, लैंड एग्रीगेटर्स और डेवलपर्स हैं, जो पिछले 15 वर्षों से उक्त व्यवसाय में हैं और पनवेल और उसके आसपास कुछ जमीनों के मालिक हैं।

बी) अपीलकर्ता के अनुसार, जनवरी 2008 में, चूंकि कंपनी पनवेल, जिले और उसके आसपास एक टाउनशिप परियोजना और एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) परियोजना विकसित करने में रुचि रखती थी। रायगढ़, महाराष्ट्र, महावीर एस्टेट एजेंसी - ब्रोकर के एक वीरेंद्र गाला ने उन्हें यहां अपीलकर्ता बी और उनके पति से पनवेल में बड़ी जमीन रखने वाले भूमि मालिकों के रूप में पेश किया। अपीलकर्ता ने कंपनी को बताया कि उक्त भूमि एक टाउनशिप परियोजना और एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के विकास के लिए आदर्श थी और उनके पास इसे अकेले विकसित करने के लिए कोई वित्तीय साधन और क्षमता नहीं है। आगे यह दर्शाया गया कि वे एक उपयुक्त व्यक्ति की भी तलाश कर रहे थे, जो उनके साथ संयुक्त रूप से उक्त भूमि को विकसित करने में रुचि रखता हो।

(सी) उपरोक्त अभ्यावेदन पर विश्वास करने पर, प्रतिवादी-कंपनी ने अपीलकर्ता और उसके पति के साथ संयुक्त रूप से उक्त डी भूमि के विकास के लिए सहमति व्यक्त की। जब प्रतिवादी-कंपनी ने उक्त भूमि के संबंध में स्वामित्व दस्तावेजों के निरीक्षण का अनुरोध किया, तो अपीलकर्ता और उसके पति रुपये की एक टोकन राशि सौंपने पर इसके लिए सहमत हुए। ई पार्टियों के बीच इस समझौते के साथ 25 करोड़

रुपये दिए गए कि यदि परियोजना सफल नहीं हुई तो उक्त राशि वापस कर दी जाएगी। इससे सहमत होते हुए, प्रतिवादी-कंपनी ने रुपये का चेक जारी किया। अपीलकर्ता और उसके पति के पक्ष में 25 करोड़ रु. हालाँकि, विभिन्न कारणों से, प्रस्तावित संयुक्त उद्यम अमल में नहीं आया और अपीलकर्ता द्वारा यह दावा किया गया कि पूरी राशि रु। प्रतिवादी-कंपनी के अनुरोध के अनुसार प्रारंभिक संयुक्त उद्यम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 25 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।

(डी) अपीलकर्ता के अनुसार, फिर से प्रतिवादी- कंपनी ने एक नई परियोजना शुरू करने और एक मिल भूमि की खरीद के लिए निविदा प्रस्तुत करने के लिए अपने बैंक से वित्तीय सुविधाएं लेने में रुचि व्यक्त की। उसी के संबंध में, प्रतिवादी-कंपनी ने यहां अपीलकर्ता और उसके पति से संपर्क किया और सूचित किया कि उनके पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। बैंक को सुविधा देने में सक्षम बनाने के लिए प्रतिभूतियाँ और बैंक को प्राप्य राशियाँ लिखित रूप में दिखानी होती हैं। इसलिए, प्रतिवादी और अपीलकर्ता के बीच एक समझौते पर रुपये का चेक दिया गया। अपीलकर्ता के पति द्वारा उनके संयुक्त खाते से 25 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। अपीलकर्ता का मामला यह है कि उपरोक्त समझ का उल्लंघन करते हुए, 05.02.2009 को, प्रतिवादी ने कफ परेड, मुंबई में आईडीबीआई बैंक में चेक जमा किया और उक्त चेक "अपर्याप्त धनराशि" के कारण बाउंस हो गया।

(ई) 18.02.2009 को, अपीलकर्ता और उसके पति को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (संक्षेप में 'एन.आई. अधिनियम') की धारा 138 के तहत एक वैधानिक नोटिस जारी किया गया था और उनसे 25 करोड़ रुपये की राशि चुकाने के लिए कहा गया था। 06.03.2009 को, अपीलकर्ता और उसके पति ने संयुक्त रूप से

उन परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए जवाब दिया जिनमें सहायक पत्रों के साथ उक्त चेक जारी किया गया था।

(एफ) 04.04.2009 को, अपीलकर्ता और उसके पति के खिलाफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, दादर, मुंबई की अदालत में एक शिकायत दर्ज की गई थी और इसे 2009 के केस नंबर 1171-एसएस के रूप में दर्ज किया गया था। आदेश दिनांक 20.04.2009 द्वारा , उनके खिलाफ प्रक्रिया जारी की गई।

(जी) 12.01.2010 को, अपीलकर्ता और उसके पति ने दस्तावेजों की प्रदर्शनी पर आपत्ति जताते हुए एक आवेदन दायर किया और इसे एक्सएच के रूप में पंजीकृत किया गया। आदेश 28. दिनांक 11.05.2010 द्वारा उक्त आवेदन खारिज कर दिया गया।

(एच) मजिस्ट्रेट द्वारा आवेदन को खारिज करने की प्रक्रिया दिनांक 20.04.2009 और आदेश दिनांक 11.05.2010 को जारी करने के खिलाफ, अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2010 की रिट याचिका संख्या 1823 दायर की। उच्च न्यायालय ने, दिनांक 24.09.2010 के आक्षेपित आदेश द्वारा, याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और दिनांक 11.05.2010 के आदेश को रद्द कर दिया और मजिस्ट्रेट को दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी के वकील द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर निर्णय लेने का निर्देश दिया, लेकिन इसे रद्द करने से इनकार कर दिया। कार्यवाही.

(i) उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता नेविशेष अनुमति के माध्यम से उपरोक्त अपील दायर किया है।

4. श्री के.वी. अपीलकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील विश्वनाथन और प्रतिवादी नंबर 1 के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी को सुना है ।

विवाद:

5. श्री के.वी. अपीलकर्ता के वरिष्ठ वकील विश्वनाथन ने हमारा ध्यान एनआई की धारा 138 की ओर आकर्षित किया। अधिनियम के साथ-साथ अभिव्यक्ति "दराज" की व्याख्या से संबंधित इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों ने प्रस्तुत किया कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जारी करना कायम नहीं रखा जा सकता है। दूसरी ओर, प्रतिवादी नंबर 1/शिकायतकर्ता के वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी ने कहा कि चूँकि वर्तमान मामला पूरी तरह से एनआई की धारा डी 141 के अंतर्गत आता है। अधिनियम और यह कि आरोपी व्यक्ति, अर्थात् आशीष शाह और अपर्णा शाह (अपीलकर्ता नंबर 1) धारा 141 के तहत परिकल्पित व्यक्तियों का एक संघ हैं, विद्वान मजिस्ट्रेट ने प्रक्रिया जारी करने में पूरी तरह से उचित ठहराया था। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी नंबर 1 के साथ लेनदेन पर दोनों आरोपियों द्वारा बातचीत की गई थी, जो चेक प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा जारी किया गया था, वह दोनों आरोपियों द्वारा बनाए गए संयुक्त खाते में जमा किया गया था, चेक पर नाम और मुहर है दोनों आरोपी और सभी सामग्रियों को छिपाकर, अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय और इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, इसलिए भौतिक तथ्यों को छिपाने/दबाने के आधार पर उसके दावे को खारिज कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने अंत में बताया कि चूँकि मुकदमा शुरू हो चुका है और अपीलकर्ता के पास मुकदमे के दौरान उसका उपचार होगा, उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में संहिता') की धारा 482 के तहत दायर उसकी याचिका को खारिज करने में सही किया था।

6. हमने प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है सभी प्रासंगिक सामग्रियों का अवलोकन किया।

बहस:

7. प्रतिद्वंद्वी विवादों को समझने के लिए यह उपयोगी है एन.आई. अधिनियम की धारा 138 का संदर्भ लें जो निम्नानुसार है:

"138. खाते में धन की अपर्याप्तता आदि के लिए चेक का अनादर। - जहां किसी व्यक्ति द्वारा किसी बैंकर के साथ रखे गए खाते पर उस खाते से किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी राशि के भुगतान के लिए निकाला गया चेक किसी भी ऋण या अन्य देनदारी का पूरा या आंशिक भुगतान बैंक द्वारा बिना भुगतान किए वापस कर दिया जाता है, क्योंकि या तो उस खाते में जमा धनराशि चेक का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त है या वह राशि से अधिक है। उस बैंक के साथ की गई व्यवस्था द्वारा उस खाते से भुगतान करने की व्यवस्था की जाती है, ऐसे व्यक्ति को अपराध माना जाएगा और इस अधिनियम के किसी भी अन्य प्रावधान पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जा सकता है जिसे दो तक बढ़ाया जा सकता है। वर्ष, या जुर्माना जो चेक की राशि के दोगुने तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों के साथ:

बशर्ते कि इस धारा में निहित कोई भी बात तब तक लागू नहीं होगी जब तक-

(ए) चेक को उसके निकाले जाने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर या उसकी वैधता की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, बैंक में प्रस्तुत किया गया है,

(बी) नियत समय में प्राप्तकर्ता या धारक जैसा भी मामला हो, चेक इसकी मांग करता है। चेक को अवैतनिक रूप में वापस करने के संबंध में बैंक से सूचना प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर, चेक जारीकर्ता को लिखित रूप में एक नोटिस देकर उक्त राशि का भुगतान करना; और

(सी) ऐसे चेक का आहर्ता प्राप्तकर्ता को उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहता है या, मामला हो सकता है, चेक के नियत समय में धारक को उक्त नोटिस की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर।

स्पष्टीकरण.-इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "ऋण या अन्य दायित्व" का अर्थ कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या अन्य दायित्व है"

8. एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध कायम करने के लिए, *जुगेश सहगल बनाम शमशेर सिंह गोगी,* **(2009) 14 एससीसी 683** में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित सामग्रियों पर ध्यान दिया, जिन्हें पूरा करना आवश्यक है:

"(i) किसी व्यक्ति ने किसी बैंक में अपने द्वारा रखे गए खाते पर उस खाते से किसी अन्य व्यक्ति को एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए चेक निकाला होगा,

(ii) चेक किसी ऋण या अन्य देनदारी के पूर्ण या आंशिक भुगतान के लिए जारी किया जाना चाहिए था;

(iii) वह चेक एक के भीतर बैंक को प्रस्तुत किया गया है। उस तारीख से छह महीने की अवधि जिस पर इसे निकाला गया है या इसकी वैधता की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो;

(iv) वह चेक बैंक द्वारा बिना भुगतान के वापस कर दिया जाता है, क्योंकि या तो खाते में जमा धनराशि चेक का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त है या बैंक उस खाते से किए गए समझौते द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि से अधिक है।

(v) चेक को अवैतनिक मानकर लौटाने के संबंध में, चेक प्राप्तकर्ता या धारक, चेक जारी करने वाले को सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर लिखित रूप में एक नोटिस देकर उक्त धनराशि के भुगतान की मांग करता है।

(vi) ऐसे चेक का भुगतानकर्ता उक्त नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर चेक के प्राप्तकर्ता या धारक को उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहता है।

संचयी होने के कारण, जब उपरोक्त सभी सामग्रियां संतुष्ट हो जाती हैं, अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध को प्रतिबद्ध माना जा सकता है।"

धारा 138 में प्रयुक्त भाषा को ध्यान में रखते हुए और उस पृष्ठभूमि समझौते को ध्यान में रखते हुए जिसके अनुसार एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा चेक जारी किया जाता है, हमारा विचार है कि केवल चेक का "आहरणकर्ता" ही दंड के लिए उत्तरदायी बनाया जा सकता है। एनआइ के प्रावधानों के तहत कार्रवाई कार्यवाही करना। यह स्थापित कानून है कि दंडात्मक कानूनों की सख्त व्याख्या की जानी आवश्यक है।

9. *जुगेश सहगल (सुप्रा)* में, मामले के तथ्यों पर धारा 138 को आकर्षित करने की सामग्री पर ध्यान देने के बाद, इस न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अधिनियम की धारा 138 के तहत आगे बढ़ने के लिए कोई मामला नहीं है। उस मामले में, 20.01.2001 को, शिकायतकर्ता ने सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 (इसके बाद "आईपीसी के रूप में संदर्भित) की धारा 420, 467, 468, 471 और 406 के तहत अपराध के लिए एफआईआर दर्ज की थी और वहां शायद ही कोई विवाद हो कि चेक, एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत की विषय-वस्तु, अपीलकर्ता द्वारा इंडियन बैंक, सोनीपत शाखा में उसके द्वारा संचालित खाते पर नहीं निकाला गया था। आवश्यक सामग्री के आलोक में धारा 138 के प्रावधानों को आकर्षित

करने के लिए, इस न्यायालय ने यह पाया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऊपर उल्लिखित एनआई अधिनियम की धारा 138 का पहला घटक संतुष्ट नहीं है और निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता के खिलाफ अपराध करने का मामला दर्ज किया गया है। धारा 138 को साबित नहीं किया जा सकता।

10. *एस.के. में अलघ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य,* (2008) 5 एससीसी 662, इस न्यायालय ने कहा:

19..... यदि और जब कोई क़ानून ऐसी कानूनी कल्पना के निर्माण पर विचार करता है, तो यह विशेष रूप से उसके लिए प्रावधान करता है। क़ानून के तहत निर्धारित किसी भी प्रावधान के अभाव में, किसी कंपनी के निदेशक या किसी कर्मचारी को कंपनी द्वारा किए गए किसी भी अपराध के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। (*देखें सबिता राममूर्ति बनाम आर.बी.एस. चन्नबसवराध्या,* (2006) 10 एससीसी 581)"

11. *शाम सुंदर और अन्य बनाम हरियाणा राज्य,* (1989) 4 एससीसी 630 में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय लिया।

"9. दंडात्मक प्रावधान को सबसे पहले सख्ती से समझा जाना चाहिए। दूसरे, आपराधिक कानून में कोई प्रतिवर्ती दायित्व नहीं है जब तक कि कानून इसे भी अपने दायरे में नहीं लेता। धारा 10 ऐसी व्यवहार्यता का प्रावधान नहीं करती है। यह सभी को लागू नहीं करती है भागीदार अपराध के लिए उत्तरदायी हैं, चाहे वे व्यवसाय करें या नहीं।"

12. जैसा कि अपीलकर्ता के वरिष्ठ वकील ने बताया है, उत्तरदाताओं द्वारा जो व्याख्या की मांग की गई है वह धारा 141 में शब्द जोड़ देगी और उन व्यक्तियों के लिए प्रतिवर्ती दायित्व के सिद्धांत का विस्तार करेगी जिनका इसमें नाम नहीं है।

13. मौजूदा मामले में, हम चेक के अनादरण के कारण आपराधिक दायित्व से चिंतित हैं। यह मुख्य रूप से दराज पर पड़ता है, यदि यह एक कंपनी है, तो दराज कंपनी पर पड़ता है और कंपनी के अधिकारियों तक बढ़ाया जाता है। आपराधिक दायित्व से जुड़े मामलों में सामान्य नियम परोक्ष दायित्व के विरुद्ध है। स्पष्ट रूप से कहें तो, किसी को भी दूसरे के कृत्य के लिए आपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। हालाँकि, यह सामान्य नियम दूसरों को दायित्व प्रदान करने वाले कानूनों में किए गए विशिष्ट प्रावधान के कारण अपवाद के अधीन है। उदाहरण के लिए, एन.आई. की धारा 141. अधिनियम विशिष्ट प्रावधान का एक उदाहरण है कि यदि किसी कंपनी द्वारा धारा 138 के तहत कोई अपराध किया जाता है, तो चेक के अनादरण के लिए आपराधिक दायित्व कंपनी के अधिकारियों पर लागू होगा। वास्तव में, धारा 141 में ऐसी शर्तें शामिल हैं जिन्हें दायित्व बढ़ाने से पहले पूरा करना होगा। चूंकि प्रावधान आपराधिक दायित्व बनाता है, इसलिए शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा। दूसरे जी शब्दों में, जिन व्यक्तियों का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है, उन्हें इसमें शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। एक कंपनी एक न्यायिक व्यक्ति है, इसके सभी कार्य और कार्य दूसरों के कृत्यों का परिणाम हैं। अत: कंपनी के अधिकारी, जो किये गये कृत्यों के लिये उत्तरदायी हैं, कंपनी के नाम पर, एच को उन कृत्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाने की मांग की जाती है जिसके परिणामस्वरूप आपराधिक कार्रवाई की जाती है। कंपनी के खिलाफ. दूसरे शब्दों में, यह प्रत्येक व्यक्ति को, जो अपराध किए जाने के समय, कंपनी का प्रभारी था और कंपनी के व्यवसाय के

संचालन के लिए जिम्मेदार था, साथ ही कंपनी को भी अपराध के लिए उत्तरदायी बनाता है। यह सच है कि उप-धारा का प्रावधान कुछ व्यक्तियों को यह साबित करने में सक्षम बनाता है कि अपराध उनकी जानकारी के बिना किया गया था या उन्होंने अपराध को रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम किए थे। एन.आई. की धारा 141 के तहत दायित्व अधिनियम को कंपनी से जुड़े एक व्यक्ति पर लागू करने की मांग की गई है, मुख्य आरोपी कंपनी ही है। यह परोक्ष दायित्व के विरुद्ध आपराधिक कानून के नियम से हटकर है।

14. यह विवाद में नहीं है कि पहले प्रतिवादी ने दंड संहिता के किसी अन्य प्रावधान के तहत कोई शिकायत दर्ज नहीं की है और इसलिए, पार्टियों के इरादे से संबंधित तर्क पूरी तरह से गलत है। हमें धारा 138 के प्रावधानों के तहत जारी नोटिस, उस पर दिए गए जवाब, शिकायत की प्रति और आदेश जारी करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। इस संबंध में, प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी ने यहां अपीलकर्ता और उसके पति की संलिप्तता के बारे में बताने के बाद तर्क दिया कि उन्हें उनकी जानकारी में भौतिक तथ्यों को छिपाने/दबाने के आधार पर कोई आपत्ति उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उक्त उद्देश्य के लिए, उन्होंने ओसवाल फैट्स एंड ऑयल्स लिमिटेड बनाम अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), बरेली डिवीजन, बरेली और अन्य, (2010) 4 एससीसी 728, बलवंतराय चिमनलाल त्रिवेदी बनाम एम.एन. पर भरोसा किया। नागराश्ना एवं अन्य, एआईआर 1960 एससी 1292, जे.पी. बिल्डर्स एवं अन्य। बनाम ए. रामदास राव एवं अन्य, (2011) 1 एससीसी 429। चूँकि अपीलकर्ता ने प्रासंगिक सामग्री संलग्न की थी, अर्थात् नोटिस की प्रति, उत्तर की प्रति, शिकायत की प्रति और आदेश जारी करने की प्रक्रिया जो अकेले ही प्रासंगिक है एन.आई. की धारा 138 के तहत शिकायत के संबंध में विचार हेतु। अधिनियम,

प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान वरिष्ठ वकील का यह तर्क कि भौतिक तथ्यों या प्रासंगिक तथ्यों को दबाने के लिए अपीलकर्ता के रुख को खारिज कर दिया जाना चाहिए, टिक नहीं सकता। ऐसी परिस्थितियों में हमारा मानना है किप्रतिस्पर्धी प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा जिस केस कानून पर भरोसा किया गया है वह वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।

15. प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी ने जनरल क्लॉजेज एक्ट, 1897 की धारा 3(42) में "व्यक्ति" की परिभाषा की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि उल्लिखित विभिन्न परिस्थितियों को देखते हुए, यहां अपीलकर्ता पत्नी होने के नाते आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि एन.आई. की धारा 141(2) में स्पष्टीकरण के मद्देनजर। अधिनियम के अनुसार, अपीलकर्ता पत्नी पर व्यक्तिगत संघ के रूप में मुकदमा चलाया जा रहा है। हमारे विचार में, उपरोक्त सभी तर्क अस्वीकार्य हैं क्योंकि विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर शिकायत में प्रतिवादी नंबर 1 का मामला कभी नहीं था कि अपीलकर्ता पत्नी पर व्यक्तियों के एक संघ के रूप में मुकदमा चलाया जा रहा है और इसलिए, अकेले इस आधार पर, उपरोक्त प्रस्तुतीकरण अस्वीकार किये जाने योग्य है। चूँकि, इस अभिव्यक्ति को परिभाषित नहीं किया गया है, धारा 141 में शामिल प्रतिवर्ती दायित्व के सिद्धांत के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इसकी व्याख्या की जानी चाहिए। शब्द "शिकायत", "व्यक्ति" "व्यक्तियों का संघ" "कंपनी" और "निर्देशकों" को इस न्यायालय ई द्वारा रघु लक्ष्मीनारायणन बनाम फाइन ट्यूब्स, (2007) 5 एससीसी 103 में समझाया गया है।

16. धारा 138 के संदर्भ में उपरोक्त चर्चा और वैधानिक नोटिस, उत्तर, शिकायत की एफ प्रति, आदेश, प्रक्रिया जारी करने आदि से ली गई सामग्री स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि केवल चेक जारी करने वाला ही इसके लिए जिम्मेदार है।

17. हमारे निष्कर्ष के अलावा, इस मुद्दे पर विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए कुछ निर्णयों का उल्लेख करना उपयोगी है।

18. मद्रास उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने *देवेन्द्र पुंडीर बनाम राजेंद्र प्रसाद मौर्य, मालिक, सत्यमेव एक्सपोर्ट्स पुत्र स्व. श्री रमा शंकर मौर्य,* 2008 क्रिमिनल लॉ जर्नल 777, इस न्यायालय के निर्णयों के बाद, ने इस प्रकार किया।

"7. इस न्यायालय का सुविचारित दृष्टिकोण है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उद्धृत निर्णय में दिए गए कानून के उपरोक्त प्रस्ताव तत्काल मामले के तथ्यों पर पूरी तरह से लागू होते हैं। इस मामले में भी, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है , पहला आरोपी निश्चित रूप से "कामाक्षी एंटरप्राइजेज" नाम की कंपनी का एकमात्र मालिक है और इस प्रकार, दूसरे आरोपी को धारा 138 के तहत पहले आरोपी द्वारा किए गए अपराध के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराए जाने का सवाल है। परक्राम्य लिखत अधिनियम का तो कोई सवाल ही नहीं उठता।" इतना कहने के बाद, विद्वान एकल न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को रद्द कर दिया और न्यायिक मजिस्ट्रेट को दूसरों के संबंध में मुकदमे को आगे बढ़ाने और तेज करने की अनुमति दी।

19. *गीता बेरी बनाम जेनेसिस एजुकेशनल फाउंडेशन,* 151 (2008) डीएलटी 155 में याचिकाकर्ता की पत्नी थी और उसने एनआई की धारा 138 के तहत दायर शिकायत को रद्द करने की मांग करते हुए संहिता की धारा 482 के तहत एक याचिका दायर की

थी। कार्यवाही करना। याचिकाकर्ता का मामला यह था कि अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध केवल इस आधार पर उसके खिलाफ नहीं बनाया गया है कि वह अपने पति के साथ संयुक्त खाताधारक थी। यह बताया गया कि उसने न तो संबंधित चेक काटा है और न ही जारी किया है और इसलिए, उसके अनुसार, उसके खिलाफ शिकायत कायम रखने योग्य नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह नोट करने के बाद कि शिकायत केवल अधिनियम की धारा 138 के तहत थी, न कि धारा 420 आईपीसी के तहत और यह इंगित करते हुए कि शिकायतकर्ता से इस आशय का कुछ भी पता नहीं चला कि याचिकाकर्ता चेक के लिए जिम्मेदार था। प्रश्न में, याचिकाकर्ता के रूप में कार्यवाही को रद्द कर दिया।

20. *श्रीमती बंददीप कौर बनाम एस अवनीत सिंह,* (2008) 2 पीएलआर 796, एक ऐसी ही स्थिति में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि यदि चेक जारीकर्ता नोटिस प्राप्त होने पर भुगतान करने में विफल रहता है , तो अधिनियम की धारा 138 के प्रावधानों को आकर्षित किया जा सकता है। उसके खिलाफ ही. विद्वान एकल न्यायाधीश ने आगे कहा कि यद्यपि चेक एक संयुक्त बैंक खाते में आहरित किया गया था, जिसे किसी के द्वारा संचालित किया जाना था, यानी याचिकाकर्ता या उसके पति द्वारा, लेकिन विवादास्पद दस्तावेज चेक है, जिसके अनादरण के संबंध में दायित्व तय किया जा सकता है। इसकी दराज पर के ऐसा कहने के बाद, विद्वान एकल न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता की याचिका स्वीकार कर ली और कार्यवाही को रद्द कर दिया क्योंकि यह उससे संबंधित थी और शिकायतकर्ता को दूसरों के खिलाफ आगे बढ़ने की अनुमति दी।

21. पिछले पैराग्राफ में चर्चा किए गए सिद्धांतों के प्रकाश में, हम मद्रास, दिल्ली और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालयों के विद्वान न्यायाधीशों द्वारा व्यक्त किए गए विचार का पूरी तरह से समर्थन करते हैं।

22. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हम मानते हैं कि अधिनियम की डी धारा 138 के तहत, केवल चेक जारी करने वाले पर ही मुकदमा चलाया जा सकता है। मौजूदा मामले में, माना जाता है कि अपीलकर्ता चेक जारी करने वाली नहीं है और उसने उस पर हस्ताक्षर भी नहीं किए हैं। चेक की एक प्रति हमारे संज्ञान में लाई गई, हालांकि इसमें अपीलकर्ता और उसके पति का नाम शामिल है, तथ्य यह है कि उसके पति ने अकेले ही अपने हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा, शिकायत को ध्यान से पढ़ने के साथ-साथ शिकायतकर्ता के मुख्य परीक्षा-प्रमुख के हलफनामे को पढ़ने और चेक को देखने से पता चलेगा कि अपीलकर्ता ने चेक पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

23. हम यह भी मानते हैं कि एन.आई. की धारा 138 के तहत अधिनियम, में संयुक्त खाते, संयुक्त खाते से चेक जारी करने का मामला धारक पर तब तक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जब तक कि चेक पर संयुक्त खाताधारक प्रत्येक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर न किया गया हो। उक्त सिद्धांत एन.आई. की धारा 141 का अपवाद है। अधिनियम जी जिसका मौजूदा मामले में कोई उपयोग नहीं होगा। धारा 138 के तहत दायर कार्यवाही को अपीलकर्ता से कथित रूप से देय राशि की वसूली के लिए हाथ घुमाने की रणनीति के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यह नहीं कहा जा सकता कि शिकायतकर्ता के पास अपीलकर्ता के खिलाफ कोई उपाय नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से धारा 138 के तहत नहीं। किसी भी मामले में चेक के अनादरण से जुड़ा एच दोषी नहीं हो सकता। "एन.आई. अधिनियम की धारा 141 के मामले को

छोड़कर" उन लोगों तक बढ़ाया जाए जिनकी ओर से चेक जारी किया गया है। यह अदालत दोहराती है कि केवल चेक जारी करने वाले को ही अधिनियम की धारा 138 के तहत किसी भी कार्यवाही में आरोपी बनाया जा सकता है। यहां तक कि उच्च न्यायालय ने भी विशेष रूप से अपीलकर्ता के रुख को दर्ज किया है कि वह चेक की हस्ताक्षरकर्ता नहीं थी, लेकिन इस तर्क को खारिज कर दिया कि राशि उसके द्वारा देय नहीं थी और केवल इस आधार पर देय थी कि मुकदमा प्रगति पर है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रक्रिया जारी होने के बाद ही, कोई व्यक्ति अपने लिए उपलब्ध विभिन्न आधारों पर इसे रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। तदनुसार, उच्च न्यायालय यह मानने में स्पष्ट रूप से गलत था कि अपीलकर्ता की प्रार्थना पर विचार भी नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने स्वयं मजिस्ट्रेट को दस्तावेजों को स्वीकार/अस्वीकार करने की प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया है। ऐसे में यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि ट्रायल एडवांस स्टेज में है।

24. इन परिस्थितियों में, अपील की अनुमति दी जानी चाहिए और विद्वान मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट 13 वीं अदालत, दादर, मुंबई की अदालत के समक्ष लंबित आपराधिक मामले संख्या 1171/एसएस/2009 में प्रक्रिया को रद्द किया जाना चाहिए, तदनुसार, यहां अपीलकर्ता के खिलाफ खारिज कर दिया जाना चाहिए।

अपील स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक **कौशल वर्मा** (न्यायिक अधिकारी) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः- यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।